समक्ष स्वतंत्र कुमार और राजीव भल्ला जे.जे.

कैलाश बाई @ कैलाश रानी - याचिकाकर्ता

बनाम

अतिरिक्त. सिविल जज (एस.डी.), टोहाना और अन्य -प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. क्र. संख्या 4794 ऑफ़ 2004

19 अगस्त, 2004

हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 नियम - 41, 49 और 65- भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226 - सरपंच पद के लिए चुनाव - याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित किया गया- प्रतिवादी 2 द्वारा चुनौती - ट्रायल कोर्ट ने वोटों की जांच दोबारा करने के बाद प्रतिवादी को निर्वाचित घोषित किया- नियम 41 के प्रावधान में मतदान कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मतपत्रों के पीछे दिखाई देने वाली मोहर को भरें - मतदान कर्मचारियों द्वारा मोहर न भरना - ट्रायल कोर्ट ऐसे वोटों को अवैध घोषित कर सकते है - क्या मतदान कर्मचारियों की ओर से मतपत्रों के ऊपर स्टाम्पों को लगाने की विफलता को अमान्य माना जाता है - **अभिनिर्णित** , नहीं - बूथ कैप्चरिंग या धांधली का कोई आरोप नहीं - कर्मचारियों द्वारा स्टाम्प न भरना प्रामाणिक गलती है - न तो 1994 के नियमों का कोई प्रावधान है और न ही निर्देश/आयोग द्वारा जारी निर्देशों में मतदान कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटियों के आधार पर मतपत्रों को अस्वीकार करने का आदेश दिया गया है - प्रतिवादी को निर्वाचित सरपंच घोषित करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया गया है।

अभिनिर्णित - नियम 41 के अनुसार मतदान कर्मचारियों को मतपत्र के पीछे की तरफ दिखने वाली मोहर भरनी होगी। हालाँकि, न तो नियम 41, न ही नियम 65 और न ही नियमों का कोई अन्य प्रावधान यह कहता है कि मतदान कर्मचारियों द्वारा टिकट भरने में विफलता के कारण मतपत्र को खारिज कर दिया जा सकता है। केवल इसी वजह से मतपत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है कि पीछे की तरफ दिखाई देने वाला स्टांप भरा नहीं गया है जब तक किसी वैधानिक आदेश में यह नहीं लिखा हुआ कि स्टांप न भरने पर मतपत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा । प्रतिवादी का मामला यह नहीं है कि कोई दुर्भावना या धांधली हुई थी या नकली मतपत्र डाले गए थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मतपत्रों के पीछे दिखाई देने वाली मोहर को न भरने में त्रुटि, मतदान कर्मचारियों द्वारा की गई एक वास्तविक त्रुटि थी और उक्त त्रुटि का उपयोग वोटों को अस्वीकार करने और डाले गए वोटों को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 24)

इसके अलावा, यह माना गया कि एक बार डाले गए मतपत्र को केवल नियम 65(1) के प्रावधानों के अनुसार खारिज किया जा सकता है। मतदान दल के कारण मतपत्र में किसी दोष/त्रुटि या किसी दोष के मामले में, जैसा कि नियम 65(1) के परंतुक में परिकल्पित है, ऐसे दोषों को नियम 65(1) के दो परंतुकों के संदर्भ में माफ कर दिया जाएगा। बशर्ते ऐसी गलतियाँ/त्रुटियाँ प्रामाणिक हों और बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतपत्र आदि के कोई आरोप न हों।

(पैरा 25)

इसके अलावा, यह माना गया कि मतदान कर्मचारियों द्वारा स्टाम्प न भरना, दुर्भावना, बूथों में धांधली आदि के किसी भी आरोप के अभाव में नियम 65 के पहले प्रावधान के संदर्भ में माफ किए जाने योग्य त्रुटि होगी। 1). किसी त्रुटि के कारण या मतदान कर्मचारियों की लापरवाही के कारण किसी मतदाता को उसके लोकतांत्रिक कानूनी अधिकार से या किसी उम्मीदवार को उसके वैध परिणाम से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई मतदान अधिकारी किसी मतदाता/उम्मीदवार के पास जाने में चूक करता है, जिसके प्रतिकूल परिणाम होते हैं, तो यह अक्षमता को वैधता के साथ जोड़ देगा। कोई भी कानून किसी दूसरे व्यक्ति की चूक या लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। मतदान दल की त्रुटियों को वैधानिक चूक की श्रेणी में लाकर सम्मानित नहीं किया जा सकता, जिससे वोट अमान्य हो जाएगा। परिणामस्वरूप, हमारा मानना है कि किसी भी गंभीर आरोप के अभाव में, कि बूथ पर धांधली हुई थी या मतपत्र के पीछे की तरफ दिखाई देने वाली मोहर को भरने में मतदान कर्मचारियों की विफलता के कारण किसी वोट को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। वोट फर्जी थे आदि.

(पैरा 26)

एस.के. गर्ग नरवाना - याचिकाकर्ता के वकील ।

विजय दहिया, सहायक एडवोकेट जनरल, हरियाणा।

सुश्री रूपिंदर कौर थिंद - प्रतिवादियों की ओर से वकील ।

निर्णय

राजीव भल्ला, जे,

(1) याचिकाकर्ता ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर इस रिट याचिका के माध्यम से, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), टोहाना के दिनांक 13 मार्च, 2004 के आदेश (अनुलग्नक पी-1) को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी रिट जारी करने की मांग की है।

(2) तथ्यों का संक्षिप्त विवरण उपयुक्त होगा :-

(3) ग्राम मुस्सा खेड़ा, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद के सरपंच पद के लिए चुनाव 12 मार्च, 2000 को हुए थे । कैलाश बाई उर्फ कैलाश रानी (याचिकाकर्ता), भगन बाई, मलकियत कौर और कृष्णा देवी (प्रतिवादी संख्या 2) से 4) ने चुनाव लड़ा। कुल वोट 844 पड़े। याचिकाकर्ता को 317 वोट हासिल कर निर्वाचित घोषित किया गया। उत्तरदाताओं संख्या 2, 3 और 4 को क्रमशः 306, 152 और 48 वोट मिले और 21 वोट खारिज कर दिए गए।

(4) भगन बाई (प्रतिवादी संख्या 2) ने सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), टोहाना (प्रतिवादी संख्या 1) के समक्ष चुनाव याचिका संख्या 64 दिनांक 28 मार्च, 2000 के माध्यम से उक्त चुनाव को रद्द कर दिया।

(5) अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), टोहाना ने अपने आदेश दिनांक 19 जुलाई, 2003 के तहत वोटों की पुनर्गणना का आदेश दिया।' पुनर्गणना के अनुसरण में और दिनांक 20 अगस्त, 2003 के आदेश के अनुसार, प्रतिवादी सं. 2 भगन बाई को निर्वाचित घोषित किया गया क्योंकि उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त 273 वैध वोटों की तुलना में 277 वैध वोट मिले। नतीजतन, याचिकाकर्ता का चुनाव रद्द कर दिया गया और प्रतिवादी नं. 2 को ग्राम पंचायत का निर्वाचित सरपंच घोषित किया गया।

(6) उपरोक्त आदेश को 2003 की सिविल रिट याचिका संख्या 1342 के माध्यम से लागू किया गया था।

(7) इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने दिनांक 19 फरवरी, 2004 (अनुलग्नक पी-2) के फैसले के तहत 20 अगस्त, 2003 (अनुलग्नक पी-2) के आदेश को रद्द कर दिया, और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को भेज दिया। पीठासीन अधिकारी वोटों की नए सिरे से जांच करने और मामले को नए सिरे से तय करने का निर्देश दे रहे थे।

(8) विद्वान अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), टोहाना ने मतपत्रों की नए सिरे से जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता को 301 वोट मिले थे जबकि प्रतिवादी संख्या 2 को 303 वोट मिले थे और इसलिए उसे प्रतिवादी संख्या 2 को निर्वाचित सरपंच के रूप में घोषित किया गया।

(9) चुनाव याचिका पर निर्णय लेते समय, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुल मिलाकर 44 वोट खारिज किए जा सकते हैं। चूंकि वर्तमान चुनाव याचिका याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच विवाद तक ही सीमित है और चूँकि अन्य उम्मीदवारों द्वारा डाले गए अस्वीकृत वोटों से उनके द्वारा प्राप्त वोटों या अंतिम परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा । यहां दिए गए विवरण याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 तक ही सीमित हैं।

बूथ संख्या 86

वोटों की संख्या	**अवैध घोषित किये जाने का कारण**	**कैलाश बाई**	**भगन बाई**
32	स्टाम्प पीछे की ओर बिना भरा हुआ दिखाई दे रहा है	11	6
2	मतदाता ने अंगूठा लगाया	2	
4	निशान स्पष्ट नहीं	4	
3	स्याही कथित तौर पर अन्य स्तंभों में फैल गई, हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि ये		

	वोट शुरू में किस उम्मीदवार को दिए गए थे।		

बूथ संख्या 87

वोटों की संख्या	**अवैध घोषित किये जाने का कारण**	**कैलाश बाई**	**भगन बाई**
3	स्याही अन्य स्तंभों में फैल गई	2	

(10) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अमान्य/अस्वीकृत किए गए वोटों तक लगाए गए आदेश को चुनौती दी। यह तर्क दिया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने 32 वोटों को गलत तरीके से खारिज कर दिया, इस आधार पर कि इन मतपत्रों के पीछे ब्लॉक, ग्राम पंचायत का नाम और बूथ नंबर दिखाने वाली मोहर खाली छोड़ दी गई थी। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इन मतपत्रों को खारिज करते समय हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 49 और 65 (1)(e) के प्रावधानों पर भरोसा किया, लेकिन पहले प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया। नियम 65 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया

है कि यदि संबंधित पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी द्वारा कोई गलती या विफलता हुई है, तो इस दोष को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और मतपत्र को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त परंतुक का अवलोकन किया होता, तो उसने मतपत्रों को खारिज नहीं किया होता।

(11) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे बताया कि 32 मतपत्रों में से जो स्टांप भरने में विफलता के कारण खारिज कर दिए गए थे, 11 याचिकाकर्ता के पक्ष में और 6 प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में मतदान किए गए थे और शेष अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में। याचिकाकर्ता ने **जिबोनतारा घाटोवार बनाम सर्बनाडा सोनोवाल और अन्य**[1], नामक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा जताया है, जहां, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उत्पन्न एक समान विवाद में, यह माना गया था कि मुहर लगाने, भरने और हस्ताक्षर करने और पीछे की तरफ मतपत्र पर हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी उसी की है। मतदान कर्मचारी किसी मतपत्र को इस आधार पर खारिज नहीं कर सकते कि मोहर खाली छोड़ दी गई है।

(12) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने गलती से कुछ मतपत्रों को खारिज कर दिया है, यह पाते हुए कि स्याही अन्य कॉलमों में फैल गई थी, जिससे वोट अमान्य हो गए। यदि ट्रायल कोर्ट ने नियमों के नियम 65(1) के दूसरे प्रावधान

---

[1] (2003) 6 S.C.C. 452

का अवलोकन किया होता, तो इन मतपत्रों को खारिज नहीं किया जा सकता था। उक्त प्रावधान में कहा गया है कि यदि किसी मतदाता द्वारा लगाए गए निशान की स्याही मतपत्र के अन्य कॉलमों में फैल जाती है, तो वोट उस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाएगा जिसके कॉलम में निशान का बड़ा हिस्सा गिरता है। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा इस परंतुक की अनदेखी की गई है।

(13) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों/निर्देशों को भी हमारे ध्यान में किया है। इन निर्देशों का शीर्षक 'गिनती' है। इन निर्देशों के अध्याय 6.1 पैरा 17(4)(6) में मतदान अधिकारियों द्वारा भरे जाने वाले स्टांप को खाली छोड़ने की संभावना की परिकल्पना की गई है। ऐसी स्थिति में, निर्देश हैं कि मतपत्रों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त निर्देशों के पैरा 17(4) में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि यदि मतपत्र को गलत तरीके से मोड़ने के परिणामस्वरूप स्याही अन्य कॉलमों में फैल जाती है, जिससे उन कॉलमों में एक निशान दिखाई देता है, तो इसका असली उद्देश्य क्या है, तीर की दिशा देखकर मतदाता का अनुमान लगाया जा सकता है।

(14) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 32 वोट जिनमें स्टांप खाली था, ट्रायल कोर्ट द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि मतपत्र के पीछे दिखाई देने वाले स्टाम्प को न भरना नियम 41 का उल्लंघन है, न कि नियमों के नियम 49 का और इसलिए नियम 65 (1) का पहला प्रावधान अनुपयुक्त है। आगे यह

तर्क दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले से ही निर्धारित तथ्यों के प्रश्न की जांच नहीं करनी चाहिए और इसलिए वर्तमान रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(15) इस न्यायालय के 25 मार्च, 2004 और 20 अप्रैल, 2004 के आदेशों के तहत, इन उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए वोटों, गिने गए वोटों और खारिज किए गए वोटों सहित पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया था। वोटों वाले सीलबंद लिफाफे को भी खोला गया और अस्वीकृत वोटों की एक-एक करके जांच की गई।

(16) इससे पहले कि हम गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच करें, प्रासंगिक नियमों को दोबारा प्रस्तुत करना उचित होगा:

> **"41. मतपत्र का स्वरूप -** प्रत्येक मतपत्र ऐसे डिजाइन का होगा जिसे राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जा सके। हालाँकि, पूरे हरियाणा राज्य में पंचों, सरपंचों, पंचायत समितियों के सदस्यों और जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव के लिए मतपत्र चार अलग-अलग रंगों में होंगे। संबंधित उम्मीदवार का नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में उसके चुनाव चिह्न के सामने उसी क्रम में लिखा जाएगा, जिस क्रम में वह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में लिखा है। मतपत्र के पीछे की तरफ पंच के चुनाव के मामले में वार्ड की संख्या और मतदान केंद्र की संख्या, पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव के मामले में गांव का नाम और

मतदान केंद्र की संख्या और वार्ड की संख्या और जिला परिषद के सदस्य के चुनाव के मामले में, जैसा भी मामला हो, मतदान केंद्र की संख्या लिखी जाएगी।

49. मतपत्र जारी करना- (1) मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से पहले किसी भी मतदाता को कोई मतपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(2) मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के बाद किसी भी मतदाता को कोई मतपत्र जारी नहीं किया जाएगा, केवल उन मतदाताओं को छोड़कर जो मतदान समाप्ति के समय मतदान केंद्र पर मौजूद थे। ऐसे मतदाताओं को मतदान का समय समाप्त होने के बाद भी वोट डालने की अनुमति दी जाएगी।

(3) प्रत्येक मतपत्र पर, मतदाता को जारी करने से पहले, ऐसे विशिष्ट चिह्न के साथ चिह्नित किया जाएगा जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) निर्देशित कर सकता है।

(4) जिस मतदान केंद्र पर एक से अधिक पदाधिकारियों के लिए मतदान होना है, वहां प्रत्येक मतदाता को ऐसे विभिन्न कार्यालयों के लिए मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

(5) किसी मतदाता को मतपत्र जारी करते समय, मतदान अधिकारी इस प्रयोजन के लिए अलग रखी गई मतदाता सूची की प्रति में मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के सामने उसका क्रमांक दर्ज करेगा।

(6) उप-नियम (5) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, मतदान केंद्र में कोई भी व्यक्ति किसी विशेष मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या को नोट नहीं करेगा।

65. मतपत्रों की जांच और अस्वीकृति-(1) मतपेटी में मौजूद मतपत्र खारिज कर दिया जाएगा, यदि-

(a) उस पर कोई निशान या लिखावट हो जिससे मतदाता की पहचान की जा सके;

(b) यह एक नकली मतपत्र है; '

(c) यह इतना क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया है कि वास्तविक मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है;

(d) उस पर क्रमांक अंकित है, या उसका डिज़ाइन विशिष्ट मतदान केंद्र पर उपयोग के लिए अधिकृत मतपत्र के क्रमांक, जैसा भी मामला हो, या डिज़ाइन से भिन्न है;

(e) उस पर कोई निशान नहीं है जो उसे नियम 49 के उप-नियम (3) के प्रावधानों के तहत होना चाहिए;

(f) इसे चिन्हित नहीं किया गया है;

(g) इसे एक से अधिक उम्मीदवार के कॉलम में अंकित किया गया है; या

(h) इसे एक उपकरण द्वारा और उस उद्देश्य के लिए निर्धारित उपकरण और तरीके से भिन्न तरीके से चिह्नित किया गया है;

बशर्ते कि जहां रिटर्निंग ऑफिसर, (पंचायत) या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस बात से संतुष्ट होने पर कि खंड (d) या खंड (i) में उल्लिखित किसी भी तरह की त्रुटि, मतदान में उपयोग किए गए सभी या किसी भी मतपत्र के संबंध में है। मतदान केंद्र, संबंधित पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की गलती या विफलता के कारण हुआ है, या निर्देश दिया है कि दोष की अनदेखी की जानी चाहिए, खंड (d) या खंड (i) के तहत केवल ऐसे दोष के आधार पर मतपत्र को खारिज नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि किसी मतदाता द्वारा लगाया गया निशान मतपत्र के दो कॉलमों में पढ़ा गया हो तो वोट उस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाएगा जिस कॉलम में निशान का बड़ा हिस्सा पड़ता है।

(2) उप-नियम (1) के तहत किसी भी मतपत्र को अस्वीकार करने से पहले, रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) या उसके द्वारा अधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी प्रत्येक मतगणना

एजेंट को मतपत्र का निरीक्षण करने का उचित अवसर देगा, लेकिन उसे इसे या कोई अन्य मतपत्र को संभालने की अनुमति नहीं देगा।

(3) रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) या उसके द्वारा अधिकृत ऐसा कोई अन्य अधिकारी, प्रत्येक मतपत्र पर 'आर' अक्षर और अस्वीकृति के आधार को संक्षिप्त रूप में दर्ज करेगा, चाहे वह अपने हाथ में हो या रबर टिकट के माध्यम से।

(4) इस नियम के तहत खारिज किए गए सभी मतपत्रों को एक साथ बंडल किया जाएगा।

(17) इस स्तर पर, मतदान कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटियों के आधार पर मतपत्र की अस्वीकृति के संबंध में **जोबोंटारा घाटोवार के मामले (सुप्रा)** का उल्लेख करना भी उचित होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी थी;

“14. नियमों को पढ़ने से पता चलता है कि मतदान अधिकारी पर चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित ऐसे विशिष्ट चिह्नों के साथ मुहर लगाने और मतपत्रों के पीछे पूर्ण हस्ताक्षर करने का दायित्व डाला गया है। मतदान अधिकारी द्वारा ऐसे कर्तव्य के पालन में उम्मीदवार की कोई भूमिका नहीं होती है। चिह्न और हस्ताक्षर के अभाव में मतपत्र अस्वीकार कर दिया जाता है। हालाँकि, फिर भी, जहाँ रिटर्निंग अधिकारी संतुष्ट महसूस करता है कि ऐसी खराबी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की ओर से किसी गलती या विफलता के कारण हुई है। केवल ऐसी खराबी के

आधार पर मतपत्र खारिज नहीं किया जाएगा। इस नियम का विश्लेषण और इसके कानूनी निहितार्थ हमें अब और नहीं रोक सकते क्योंकि हम पाते हैं कि इन नियमों का **अरुण कुमार बोस बनाम मोहम्मद फुरकान अंसारी, (1984) 1 SCC 91**, मामले में निपटारा किया जा चुका है। जिसमें इस न्यायालय ने पाया कि चौहत्तर मतपत्रों पर हस्ताक्षर और विशिष्ट चिह्न की अनुपस्थिति पीठासीन अधिकारी की विफलता के कारण थी। ऐसा पाए जाने पर, न्यायालय ने कहा (SCC पृष्ठ 101 पैरा 14):

"मतदाताओं को मतपत्र जारी करने से पहले उन पर अपने हस्ताक्षर करना पीठासीन अधिकारी का दायित्व था। प्रत्येक मतदाता को वोट देने का अधिकार है और देश में प्रचलित लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार साझा करने के हकदार किसी भी व्यक्ति को इस विशेषाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। न ही अभ्यर्थी को कष्ट पहुंचाया जा सकता है. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारा निश्चित मानना है कि वर्तमान मामला पीठासीन अधिकारी की ओर से उन मतपत्रों पर अपने हस्ताक्षर करने में विफलता का है ताकि कानून की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। प्रावधान, एक बार लागू होने के बाद, यह भी आदेश देता है कि मतपत्र को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, हम मानते हैं कि मतपत्र खारिज किए जाने योग्य नहीं थे क्योंकि प्रावधान लागू किया गया था और उच्च न्यायालय,

हमारी राय में, इन मतपत्रों की गिनती करने और प्रतिवादी 1 को इसका श्रेय देने में सही निष्कर्ष पर पहुंचा।

यह ध्यान रखना उचित है कि यह किसी का मामला नहीं है कि 824 मतपत्र नकली थे। मौजूदा मामला बूथ कैप्चरिंग या धांधली का नहीं है. किसी चुनावी विवाद में केवल उम्मीदवार ही नहीं होते, बल्कि उनमें रुचि रखने वाले लोग भी शामिल होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमारी तरह, चुनाव में पूरे निर्वाचन क्षेत्र का भाग्य दांव पर होता है और प्रत्येक मतदाता और प्रत्येक नागरिक की रुचि इस बात में होती है कि वह उम्मीदवार विधानसभा में वापस आ जाए जिसने बहुमत वैध वोट हासिल किये हो। किसी चुनावी विवाद का निर्णय कानून के विपरीत रियायतों पर नहीं किया जा सकता। नियम 56(2)(b) के साथ पठित नियम 38(1) के आलोक में मतपत्रों में त्रुटि का पता चलने पर, रिटर्निंग अधिकारी की संतुष्टि से इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाना था। कानून के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिए गए निर्णय को प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों या उनके चुनाव एजेंटों द्वारा दी गई रियायत उस उम्मीदवार के रास्ते में आ सकती है और कानून की एक संदिग्ध स्थिति पर विवाद कर सकती है जिसे हल और स्वीकार किया गया माना जाता है। किसी चुनावी विवाद में, कानून के विपरीत आम सहमति या चुनाव अधिकारी पर डाले गए वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफलता, जिसके

परिणामस्वरूप चुनाव के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वास्तव में चुनौती से छूट का दावा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में रिटर्निंग अधिकारी नियम 56 के खंड (g) और (h) उप-नियम (2) के नीचे पहले प्रावधान द्वारा दिए गए अपने दायित्व का निर्वहन करने में स्पष्ट रूप से विफल रहा है। इसलिए, उच्च न्यायालय से असहमत होकर, हम मानते हैं कि ये गिनती के लिए 824 मतपत्रों को शामिल किया जाना चाहिए था।"

(18) नियमों के नियम 41 में मतदान कर्मचारियों को मतपत्र के पीछे वार्ड की संख्या और मतदान केंद्र की संख्या निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, नियम 41, मतदान कर्मचारियों की ओर से उपरोक्त विवरण भरने में विफलता के लिए मतपत्र को अमान्य नहीं करता है।

(19) नियम 49(3) के अनुसार प्रत्येक मतपत्र को, मतदाता को जारी करने से पहले, ऐसे विशिष्ट चिह्न से चिह्नित किया जाना चाहिए जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) निर्देशित कर सकता है।

(20) नियम 65(1) में दिए गए विवरण के अनुसार, जिन आधारों पर एक बार मतपत्र डाला जाता है, उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है: -

(a) उस पर कोई निशान या लिखावट हो जिससे मतदाता की पहचान की जा सके;

(b) यह एक नकली मतपत्र है;

(c) यह इतना क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया है कि वास्तविक मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है;

(d) उस पर क्रमांक अंकित है, या उसका डिज़ाइन विशिष्ट मतदान केंद्र पर उपयोग के लिए अधिकृत मतपत्र के क्रमांक, जैसा भी मामला हो, या डिज़ाइन से भिन्न है;

(21) नियम 65(1) का पहला प्रावधान मतदान कर्मचारियों द्वारा एक त्रुटि की परिकल्पना करता है जबकि दूसरा प्रावधान मतदाता द्वारा चिपकाए गए निशान की स्याही दूसरे कॉलम में फैलने की संभावना की परिकल्पना करता है। इन दोनों स्थितियों में, दोनों प्रावधानों में कहा गया है कि ऐसे दोषों को माफ किया जा सकता है।

(22) नियमों को हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों द्वारा आगे पूरक किया गया है। इन निर्देशों का शीर्षक **"गिनती"** है और मतदान कर्मचारियों को वोटों की गिनती, खारिज करने आदि के तरीके के बारे में विस्तृत निर्देश जारी करते हैं। इन निर्देशों के अध्याय VI के पैराग्राफ 17 के उप-पैरा 6 में यह प्रावधान है कि यदि मतपत्र के पिछले हिस्से पर कोई विशिष्ट चिह्न या हस्ताक्षर नहीं है और यह स्पष्ट है कि गलती मतदान अधिकारी के कारण हुई है, मतपत्र खारिज नहीं किया जाएगा।

(23) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एक बार डाले गए मतपत्र को केवल तभी खारिज किया जा सकता है जब वह नियमों के नियम 65(1) में उल्लिखित दोषों से ग्रस्त हो और केवल ऐसे दोषों को माफ किया जा सकता है जैसा कि दो प्रावधानों में विस्तृत है। नियम 65(1) का पालन करें। अधिनियम या नियमों का कोई अन्य प्रावधान उन परिस्थितियों को निर्धारित नहीं करता है जिनमें मतपत्र को अस्वीकार किया जा सकता है।

(24) प्रतिवादियों के विद्वान वकील का तर्क है कि स्टाम्प को नियमों के नियम 41 के तहत भरना होगा और स्टाम्प न भरने को नियमों के नियम 65(1) के पहले प्रावधान के तहत माफ नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम 41 के अनुसार मतदान कर्मचारियों को मतपत्र के पीछे की तरफ लगी मुहर को भरना होगा। हालाँकि, न तो नियम 41, न ही नियम 65 और न ही नियमों का कोई अन्य प्रावधान यह कहता है कि मतदान कर्मचारियों द्वारा स्टांप भरने में विफलता के कारण डाले गए मतपत्र को खारिज कर दिया जा सकता है। इस प्रस्ताव के लिए किसी वैधानिक आदेश के अभाव में कि स्टांप न भरने पर मतपत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा, किसी मतपत्र को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि पीछे की ओर दिखाई देने वाला स्टांप भरा नहीं गया है। यह प्रतिवादियों का मामला नहीं है - चाहे चुनाव याचिका में हो या इस न्यायालय के समक्ष, कि कोई दुर्भावना या धांधली थी या नकली मतपत्र डाले गए थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मतपत्रों के पीछे दिखाई देने वाली मोहर को न भरने की त्रुटि, मतदान कर्मचारियों द्वारा की गई एक वास्तविक त्रुटि थी और

उक्त त्रुटि का उपयोग वोटों को अस्वीकार करने और रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

(25) नियमों, निर्देशों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त पुनरुत्पादित निर्णय को संयुक्त रूप से पढ़ने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मतपत्र, एक बार डाले जाने के बाद, केवल नियम 65(1) के प्रावधानों के अनुसार खारिज किया जा सकता है। मतदान दल के कारण मतपत्र में किसी दोष/त्रुटि या किसी दोष के मामले में, जैसा कि नियम 65(1) के प्रावधानों में परिकल्पित है, ऐसे दोषों को नियम 65(1) के दो प्रावधानों के अनुसार माफ कर दिया जाएगा। बशर्ते ऐसी गलतियाँ/त्रुटियाँ प्रामाणिक हों और बूथ कैप्चरिंग, नकली मतपत्र डालने आदि का कोई आरोप न हो।

(26) नियम 41, 49(3) और 65 के प्रावधानों के एक और अवलोकन से पता चलता है कि वैधानिक प्रावधानों का सार यह है कि, यदि मतपत्र में कोई खराबी मतदान कर्मचारियों द्वारा की गई वास्तविक त्रुटि के कारण होती है , उसे माफ किया जाना चाहिए। नियम 49(3) के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के निर्देशानुसार मतदान कर्मचारियों को एक विशिष्ट चिह्न लगाना आवश्यक है। नियम 65(1)(i) ऐसे चिह्न की अनुपस्थिति के कारण मतपत्र को अस्वीकार करने योग्य बनाता है। हालाँकि, नियम 65(1) का पहला प्रावधान इस तरह की चूक को माफ करता है। दुर्भावना, बूथों में धांधली आदि के किसी भी आरोप के अभाव में, मतदान कर्मचारियों द्वारा स्टांप न भरना, नियम 65(1) के पहले प्रावधान के अनुसार

माफ किए जाने योग्य त्रुटि होगी। किसी त्रुटि के कारण या मतदान कर्मचारियों की लापरवाही के कारण किसी मतदाता को उसके लोकतांत्रिक कानूनी अधिकार से या किसी उम्मीदवार को उसके वैध परिणाम से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई मतदान अधिकारी किसी मतदाता/उम्मीदवार से मिलने में चूक करता है जिसके प्रतिकूल परिणाम होते हैं, तो यह अक्षमता को वैधता के साथ जोड़ देगा। कोई भी कानून किसी दूसरे व्यक्ति की चूक या लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। मतदान दल की त्रुटियों को वैधानिक चूक की श्रेणी में लाकर सम्मानित नहीं किया जा सकता, जिससे वोट अमान्य हो जाएगा। नतीजतन, हमारा मानना है कि किसी गंभीर आरोप के अभाव में, कि बूथ पर धांधली हुई थी या मतपत्र के पीछे की तरफ दिखने वाले स्टाम्प को भरने में मतदान कर्मचारियों की विफलता के कारण किसी वोट को अवैध , वोट नकली थे आदि घोषित नहीं किया जा सकता है।

(27) जिबोनतारा घाटोवार के मामले (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत था। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब 824 वोट इस आधार पर खारिज कर दिए गए कि वोटों पर मुहर नहीं लगी थी कोई विशिष्ट चिह्न. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरुण कुमार बोस बनाम मोहम्मद के रूप में रिपोर्ट किए गए पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए। फुरकान अंसारी (2) ने कहा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जैसा कि हमारा है, एक चुनाव में, पूरे निर्वाचन क्षेत्र का भविष्य दांव पर होता है और इसलिए,

प्रत्येक मतदाता और प्रत्येक नागरिक को विधानसभा में वापस आने वाले अपने उम्मीदवार में रुचि होती है। जिन्होंने वैध मतों का बहुमत हासिल कर लिया है। इसलिए, किसी मतदान अधिकारी/मतदान स्टाफ के सदस्य द्वारा की गई त्रुटि के आधार पर वोटों को खारिज नहीं किया जा सकता है।

(28) हमने 32 मतपत्रों की जांच की है और धोखाधड़ी, दुर्भावना, बूथ कैप्चरिंग आदि के किसी भी आरोप के अभाव में, हमारी सुविचारित राय है कि इन 32 वोटों को खारिज नहीं किया जा सकता था और रिटर्निंग ऑफिसर ने सही गिनती की थी। ये वोट उन उम्मीदवारों के पक्ष में हैं जिनके लिए ये वोट डाले गए थे। विद्वान ट्रायल कोर्ट नियमों को सही ढंग से समझने में विफल रहा और इन वोटों को यांत्रिक तरीके से खारिज कर दिया।

(29) जहां तक विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज किए गए अन्य वोटों की बात है, तो हम मतदाता के वास्तविक इरादे को निर्धारित करने के लिए तथ्यात्मक विवाद में प्रवेश करना उचित नहीं समझते हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारे रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, हमारे लिए यह उचित नहीं होगा कि हम तथ्य के उन जटिल प्रश्नों की जांच करें जिनकी जांच ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले ही की जा चुकी है। हमारी राय में, इस न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह मतदाता के वास्तविक इरादे को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मतपत्र की जांच करके जांच शुरू करे, यानी कि क्या स्याही एक कॉलम से दूसरे कॉलम में फैल गई थी। मतदाता चिह्न सही ढंग से लगाया गया था। हमारी राय में,

इस तथ्यात्मक विवाद का निर्णय, प्रतिशत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, ट्रायल कोर्ट द्वारा सही ढंग से किया गया है और हम इससे भिन्न होने का कारण पाते हैं।

(30) इससे पहले कि हम पार्टियों के पक्ष में दिए गए संबंधित वोटों को सारणीबद्ध करने के लिए आगे बढ़ें, यह दोहराना उचित होगा कि वर्तमान रिट याचिका में विवाद केवल खारिज किए गए वोटों तक ही सीमित है, यानी तीन वर्गों के वोट- (a) सील न भरने के लिए, (b) अन्य कॉलम में स्याही फैलने के लिए और (c) निशान हल्का होने के लिए। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है, बत्तीस वोट गलत तरीके से खारिज कर दिए गए क्योंकि पीछे की तरफ दिखने वाला स्टाम्प नहीं भरा गया था। इन वोटों में से ग्यारह याचिकाकर्ता के पक्ष में और छह प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में पड़े। यदि उपर्युक्त वोटों को याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के मिलान में जोड़ दिया जाए तो याचिकाकर्ता को 312 वोट मिलेंगे और प्रतिवादी नंबर 2 को 309 वोट मिलेंगे और इसलिए, याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से बहुमत वोट हासिल करने के बाद निर्वाचित सरपंच घोषित करना होगा। नया मिलान याचिकाकर्ता के पक्ष में 312 वोट और प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में 309 वोट होगा।

(31) ऊपर जो कहा गया है उसके आलोक में और वैधानिक प्रावधानों के सावधानीपूर्वक अध्ययन के साथ-साथ मतपत्रों की जांच के बाद, हम आश्वस्त हैं कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के चुनाव को गलत तरीके से रद्द कर दिया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, ट्रायल कोर्ट के

फैसले को रद्द कर दिया जाता है, चुनाव याचिका खारिज कर दी जाती है और याचिकाकर्ता को 312 वोट हासिल करके निर्वाचित घोषित किया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)